

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १९

सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई

अंक २१

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० २३ जुलाओ, १९५५

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

दूसरी योजनाका छूटा हुआ पहलू

श्री निर्मलकुमार बोस ४ जून, १९५५ के 'विजिल' में 'योजनाका मानव पहलू' पर लिखते हुये कहते हैं कि "यह बड़ी अच्छी बात है कि दूसरी पंचवर्षीय योजनामें मानव पहलूकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।" कहनेका मतलब यह है कि उसे केवल अर्थशास्त्रियों या आंकड़ा-शास्त्रियोंकी योजना नहीं बनने देना चाहिये। उसे हमारे राष्ट्रीय जीवनकी बुनियादको छूना चाहिये; यह बुनियाद हमारा ग्रामजीवन है। वरना हम प्रो० महलनवीसकी अिन बातोंमें विश्वास करनेके भुलावेमें पड़ सकते हैं कि शराबबन्दी भारतमें असंभव है, शराब और अन्य नशीले पदार्थोंसे अधिकसे अधिक आबकारी आय प्राप्त करनी चाहिये, जरूरत हो तो संविधानको बदलकर नमक और जीवनकी दूसरी जरूरी चीजों पर भी कर लगाया जाना चाहिये—वगैरा वगैरा। अब यह तो स्पष्ट है कि ये मत जिस विचारसे पैदा हुये हैं कि पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूपमें नहीं तो मुख्यतः आर्थिक योजना है। दूसरी पंचवर्षीय योजनाको जिस छिपे भयसे बचाना चाहिये। श्री बोस अपने अपरोक्त लेखमें उस खतरकी ओर नीचेके शब्दोंमें इशारा करते हैं:

"हालांकि हमारे ग्रामीण और सामाजिक जीवनकी बुनियादमें भारी जड़ता और आलस्य फैले हुये हैं, जो विघ्न-बाधाओं या दूसरे दोषोंके रूपमें प्रकट होते हैं, फिर भी अगर हम ठीक ढंगसे काम करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम अनाप-शनाप पैसा खर्च करके या अपूरसे सत्ता चलाकर अिन कठिनाइयोंकी अपेक्षा करनेका प्रयत्न न करें, बल्कि सच्ची समस्याको हल करनेका प्रयत्न करें, जो असलमें अेक मानव समस्या है। जिसके अभावमें बुनियादसे जीवनका पुन-निर्माण तब तक मुश्किलसे संभव होगा, जब तक भारतीयोंकी वर्तमान पीढ़ी कब्रमें नहीं चली जाती और अंसी नयी पीढ़ी खड़ी नहीं होती, जिसके बचपनके दिन नदीकी बांध-योजनाओं, बड़े बड़े राजमार्गों और खादके विशाल कारखानोंके आसपास बीते हैं। सत्ताके बल पर परिवर्तन किये जा सकते हैं, लेकिन यह चीज अधिकार और हुकूमतको अेक जगह केन्द्रित करती है और अन्तमें सर्वसत्तावाद या तानाशाहीको जन्म देती है। परिवर्तन बुनियादमें हुकूमतका विकेन्द्रीकरण करके तथा लोगोंकी सुझबूझ और क्रियाशीलताको अुत्तजन और प्रोत्साहन देकर भी किये जा सकते हैं। यही अेकमात्र लोकशाहीका सच्चा मार्ग है। गांधीजीका विकेन्द्रीकरणका सिद्धान्त केवल मनुष्योंकी जरूरतकी चीजोंके अुत्पादन और वितरणसे ही संबंध नहीं रखता, बल्कि उसका केन्द्रबिन्दु सत्ताका विकेन्द्रीकरण है। अगर कोई आर्थिक योजना सत्ताके

विकेन्द्रीकरणके बिना सफल होती है, अगर बुनियादमें लोग आध्यात्मिक दृष्टिसे निर्बल रहें, तो जीवन-मान अूँचा अूँठा देनेसे भी क्या लाभ होगा? क्योंकि 'मनुष्य केवल रोटीके बल पर ही नहीं जीता' यह कथन मनुष्य-जीवनके आध्यात्मिक क्षेत्रके लिये जितना सच माना जाता है, अतना ही राजनीतिक क्षेत्रके लिये भी सच है।"

१-७-५५
(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

गांव अेक परिवार बने

[ता० ५-६-५५ को सुंढीढमिणी पड़ाव (अुत्कल) पर दिये गये प्रार्थना-प्रवचनसे।]

आज हमने इस गांवकी कहानी सुनी। यह गांव बड़ी आफतसे बचा है। अकालमें यह गांव खतम ही होने जा रहा था। हमारे देशकी हालत अंसी है कि पांच लाख देहातोंमें क्या-क्या घटनायें होती हैं, इसका अन्दाजा शहरवालोंकी नहीं हो सकता है। शहरमें अेक छोटीसी घटना हो जाती है तो वह फौरन अखबारमें आती है। लेकिन अधर गांवके गांव खतम होते जाते हैं फिर भी अखबारमें खबर नहीं आती है। लेकिन हमें यह जानकर बड़ी खुशी हुयी कि इस गांवके संकटके समय हमारे कुछ कार्यकर्ता यहां पर दौड़े आये और अुन्होंने कुछ मदद की, जिससे कि गांव बच गया। विशेष गौरवकी बात तो यह है कि यहां पर कस्तूरबा ट्रस्टका शिक्षण पाओ हुयी बहनें काम करती हैं, हिम्मतके साथ अकेली रहती हैं और गांव-गांव घूमकर गांववालोंको हिम्मत देती हैं।

जिस गांवने संकटका अनुभव किया है उसको मालूम होता है कि मिल-जुल कर काम करनेका क्या लाभ है। परमेश्वरने संकट भेजकर गांववालोंको यह सबक सिखाया कि भाइयो, तुम लोग गांवका अेक परिवार बनाकर रहो।

इस जिलेमें हमें काफी गांव सर्वस्व दानमें मिले हैं। अब अुन गांवोंमें कुल जमीन गांवकी बनेगी। काश्त करनेके लिये हर परिवारको थोड़ी-थोड़ी जमीन दी जायगी, परंतु मालकियत किसीकी भी नहीं रहेगी। जिस किसीके खेतमें मददकी जरूरत होगी वहां पर सब लोग मददके लिये दौड़े जायंगे, और अगर आगे जाकर गांववाले चाहें तो सारे गांवका अेक खेत भी बना सकते हैं। समग्र ग्राम-दान देनेसे क्या-क्या लाभ होते हैं, वह समझानेकी जरूरत है। अगर लोगोंकी अिन लाभोंका ज्ञान हो जाय तो हमारा विश्वास है कि हिन्दुस्तानमें अेक भी अंसा गांव नहीं रहेगा जो अपनी पूरी जमीन दानमें नहीं देगा।

जमीनकी मालकियत मिटाकर सारे गांवकी जमीन अेक करनेसे पहला लाभ तो यह होगा कि गांवकी दीलत बढ़ानेमें बड़ी सह-

लियत होगी। किन्तु खेतमें क्या बोना चाहिये और कितना बोना चाहिये, जिस बात पर सारे गांववाले सोचेंगे और सब मिलकर आयोजन करेंगे। गांवकी फसलका कितना हिस्सा बेचना है, जिसका भी विचार गांवकी समिति करेगी। गांवमें खेतीके सुधारके लिये क्या-क्या करना चाहिये, वह भी सोचा जायगा। किसी खास मौके पर गांवके लिये बाहरसे या सरकारसे मदद हासिल करनी है तो जैसे गांवमें मदद हासिल करनेमें सुविधा होगी। लोग व्यक्तिगत कर्ज नहीं लेंगे। जिस तरह जो सब लाभ होंगे, उस पर तो ग्रंथ लिखा जा सकता है, परंतु थोड़ेमें हम अितना ही कहेंगे कि समग्र ग्रामदानसे अपना अिहलोकका जीवन सुखी बनानेमें मदद होगी। आजकलकी भाषामें बोलना है तो हम कहेंगे कि जिससे आर्थिक आजादी प्राप्त होगी।

गांवका एक परिवार बनानेसे दूसरा लाभ यह होगा कि उस गांवमें परस्पर प्रेम बढ़ेगा और जीवनमें आनन्द आयागा। जब हम किसीका सुख-दुख समझ लेते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं तो दुख कम हो जाता है और सुख बढ़ता है। सुख और दुख दोनोंमें हिस्सा लेनेसे गांवमें आनन्द बढ़ेगा। आज परिवारमें आनन्द हासिल होता है। आनन्द जो होता है वह अनेकके सहकारसे होता है। जहां हर मनुष्य अपनेको भूल जाता है वहां पर आनन्द निर्माण होता है। जिस तरह गांवका एक परिवार बननेसे जीवनका आनन्द, रूचि और स्वाद बढ़ेगा। जिसे हम सांस्कृतिक लाभ कह सकते हैं।

गांवका एक परिवार बनानेसे बहुत बड़ा लाभ तो यह होगा कि लोगोंका नैतिक स्तर ऊपर उठेगा। झगड़े, गाली-गलौज, चोरी आदि सब कम होंगे। आप जानते हैं कि घरके अन्दर चोरी नहीं होती है। लड़केने कोजी चीज खा ली तो उसे चोरी नहीं कहा जाता है। मां लड़केसे अितना ही कहती है कि तू मुझे पूछकर खाता तो अच्छा होता। जिस तरह जहां गांवका एक घर बन जाता है वहां चोरी मिट जाती है। उससे नीति बढ़ती है। आज दुनियामें नीतिका स्तर अितना गिरा हुआ है, क्योंकि लोगोंने अपने आर्थिक स्वार्थके लिये अलग-अलग घर बना रखे हैं। परसों हमने एक भिखारीकी गठरी खोलकर देखी तो उसमें दो आने थे और एक साबुनका टुकड़ा था, लेकिन उसने अन्हें पक्की गांठ बांधकर रखा था। जिस तरह लोग अपने दो चार आने, दो सौ रुपये या दो हजार रुपये हों लेकिन पक्की गांठ बांधकर रखते हैं। फिर छीना-झपटी और चोरियां चलती हैं। लूटनेके और ठगनेके तरीके ढूँढे जाते हैं। डाक्टर भी किसी बीमारको देखनेके लिये जाता है तो कहता है कि पहले अपनी गठरी खोल। जिस तरह लोगोंने अपना एक संकुचित हृदय बनाया, छोटा घर बनाया, इसीलिये दुनियामें झगड़े चल रहे हैं। लेकिन जहां पर जमीनकी और संपत्तिकी मालिकियत मिट जाती है वहां पर मनुष्यकी नीति जरूर सुधरेगी। जिस नैतिक लाभको हम सबसे श्रेष्ठ लाभ कह सकते हैं। अगर दुनियाको यह लाभ ही तो दुनिया नाचेगी। क्योंकि आज दुनिया परेशान है। दुनियामें परस्पर स्वार्थकी जो टक्कर चलती है उससे दुनिया दुखी है और परिणामस्वरूप हिंसा खूब बढ़ गयी है। जिसलिये अगर हम गांवकी जमीन और संपत्ति गांवकी बना देते हैं, तो सारी दुनियाको नैतिक अुत्थानका रास्ता मिल जाता है।

और एक बड़ा लाभ होगा जिसे चाहे दुनियाके लोग समझें या न समझें लेकिन हिन्दुस्तानके और खासकर देहातके लोग समझ जायेंगे। जब हम कहते हैं कि यह मेरा घर है, मेरा खेत है, जिस तरह मेरा-मेरा चलता है तो मनुष्य आसक्त बन जाता है, कँदी बनता है। लेकिन जब मनुष्य 'मैं' और 'मेरा' यह

सब छोड़ देगा और यह कहेगा कि यह सब हमारा है, मेरा कुछ नहीं है, तो वह जल्दी मुक्त हो जायगा। आज सब लोगोंका मन बंधा हुआ है, क्योंकि मेरा-मेरा छूटता नहीं है। छूटनेके लिये संतोंने कभी अुपाय बताये हैं। फिर भी लोग मुक्ति नहीं पाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि घरवार सब कुछ छोड़कर चलोगे तो यह 'मैं' और 'मेरा' छूटेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिस तरह भाग जानेसे मनुष्यको मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्तिकी युक्ति तो यह है कि हम अपना घर छोटा न समझें। सारा गांव हमारा घर है और हमारा जो छोटा घर हम बनाते हैं वह भी सबका है, ऐसा समझें। मैं किसीका नहीं और कोजी मेरा नहीं, ऐसी बात करनेसे मनुष्य मुक्त नहीं होता। मनुष्य तो मुक्त तब होता है जब वह समझता है कि मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। जिसलिये हमारे पास जो कुछ है वह सारे गांवका है, मैं भी गांवका हूँ और गांव मेरा है, ऐसी भावना जब बनती है तब मनुष्य आसानीसे मुक्त होता है। यह एक बहुत बड़ा लाभ है।

विनोबा

तीसरे सेक्टरके लिये योजना

[तीसरा सेक्टर, जैसा कि अिन पत्रोंमें पहले विस्तारसे समझा चुके हैं, ('हमारी अर्थ-रचनाका तीसरा क्षेत्र'—हरिजनसेवक, १-१-५५) खादी और दूसरे छोटे पैमानेवाले ग्रामोद्योगोंका राष्ट्रीय सेक्टर है, जो कि हमारी राष्ट्रीय आयका अधिकांश देता है। ये अुद्योग हमारी राष्ट्रीय अर्थरचनाके सबसे ज्यादा मानवीय और जनतांत्रिक सेक्टरका निर्माण करते हैं। बाकी दो सुविदित सेक्टरोंमें—यानी जिन्हें पब्लिक या सरकारी और प्राइवेट या खानगी कहा जाता है उनमें—यह बात नहीं है। खेती, खादी और ग्रामोद्योगोंको खानगी सेक्टरमें गिनना, जैसा कि कुछ लोग भ्रमवश करते हैं, गलत है। ये अुद्योग श्रम-प्रधान होनेके कारण जनताके जीवनको सबसे ज्यादा छूते हैं। दूसरे दो सेक्टर, जो पूंजी या जैसे ही अन्य भौतिक साधनोंकी मदद पर चलते हैं, लोगोंके जीवनसे अुतना ताल्लुक नहीं रखते। जिसलिये सच्ची राष्ट्रीय और मानवीय योजनाको अपना ध्यान मुख्यतया जिस तीसरे सेक्टर पर ही केन्द्रित करना चाहिये। जिसे अभी योजना कहा जाता है, वह तो कुछ बड़े पैमानेवाले सरकारी अुद्योग खोलनेका ही कार्यक्रम है जिसमें साथ साथ खानगी अुद्योगोंको भी रहने दिया जायगा। जो हो, यह अच्छा है कि सरकार तीसरे सेक्टरको कुछ महत्त्व तो देने लगी है। उसे जिस सेक्टरकी ओर और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिये। दूसरी पंचवार्षिक योजना मुख्यतया जिस सेक्टरके आसपास संघटित की जानी चाहिये। बड़े अुद्योग, बाहरी तौर पर कितने भी बड़े क्यों न मालूम हों, आखिर तो वे स्वाश्रय और स्वावलम्बन पर आधारित राष्ट्रकी बुनियादी अर्थरचनाके गीण अंशमात्र हैं। अतः अन्हें केन्द्रीय प्रधानता नहीं मिलना चाहिये। अगर हम जिस योजनाको सचमुच जनतांत्रिक बनाना चाहते हैं, तो अितना कम-से-कम होना ही चाहिये। अन्यथा वह राज्यकी अथवा खानगी पूंजीपतियोंकी पूंजीवादी योजना ही होगी।

अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्डने हमारी अर्थ-योजनाके जिस महत्त्वपूर्ण तथ्यको प्रकाशमें लानेके लिये जो साहसपूर्ण प्रयत्न किये हैं, नीचे उनका विवरण दिया जा रहा है। उससे कम-से-कम यह बात स्पष्ट होगी कि हमें पश्चिमकी नकल करके राष्ट्रका पैसा बाहरी आकर्षणवाले कार्योंमें बरबाद करनेकी जरूरत नहीं है।

१०-६-५५

—५० प्र०]

दूसरी पंचवार्षिक योजनाके लिये अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्डने जो विकास-योजनाओं तैयार की हैं, वे बतलाती हैं कि १४२.७६ करोड़ रुपयेकी कुल पूंजीके द्वारा ८८.५८ लाख लोगोंको पूरे समयका और अिनके सिवा लगभग ८०,००० लोगोंको आंशिक समयका काम दिया जा सकता है। ये योजनाओं सूती कपड़ा, अून, चावलकी हाथ-कुटाजी, देहाती तेल, चमड़ा, गुड़ और खांडसारी, दियासलाजी, साबुन और हाथ-कागजके अुद्योगोंसे संबंध रखती हैं। बोर्डने ये योजनाओं अिस बातको मानकर बनायी हैं कि प्रत्येक अुद्योगके लिये अुत्पादनका सम्मिलित कार्यक्रम निर्धारित किया जायगा। यह जानकारी अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्डको अुसके अध्यक्षने २ जून, १९५५ को दी।

बोर्डके अध्यक्षने योजना कमीशनके अुपाध्यक्ष श्री व्ही० टी० कृष्णमाचारीके साथ बोर्ड और कम्प्यूनिटी प्रोजेक्ट्स अेडमिनिस्ट्रेशनकी प्रवृत्तियोंके संयोजनके बारेमें, खासकर प्रोजेक्ट और अेक्सटेंशन योजनाओंके क्षेत्रोंमें खादी और दूसरे ग्रामोद्योगोंके विकासके मुद्दे पर जो विचार-विमर्श किया था अुसका जिक्र किया। अुन्होंने सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग विकास कमीशनके निर्माणके लिये जो बिल पेश किया गया है, अुसका अुल्लेख किया और बतलाया कि अिस बिलका पाठ अुन्हीं शब्दोंमें रखा गया है जिन शब्दोंमें अुसे बोर्डने सुझाया था। यह कमीशन अेक स्टेच्यूटरी यानी कानूनके अनुसार अपना शासन आप करनेवाली समिति होगी और वर्तमान बोर्ड अिस कमीशनकी सलाहकार समितिकी तरह काम करता रहेगा।

यह बताया गया कि दूसरी पंचवार्षिक योजनामें सूती कपड़ा, अून, चावलकी हाथ-कुटाजी, देहाती तेल, चमड़ा, गुड़ और खांडसारी, दियासलाजी, साबुन और हाथ-कागजके लिये अुत्पादनके सम्मिलित कार्यक्रम रखनेका सोचा गया है। अिन अुद्योगोंके विकासके लिये पांच सालमें सब मिलाकर १४२.७६ करोड़ रुपयेकी पूंजी लगेगी और और ८८.५८ लाख मनुष्योंको पूरे समयका तथा ८०,००० को आंशिक समयका काम दिया जा सकेगा। अिस कार्यक्रमका सूती कपड़ेवाला हिस्सा अिस बोर्ड और हाथ-करघा बोर्डके बीचके सहकार पर निर्भर रहेगा। खादी बोर्डने यह विचार पेश किया है कि अुसका सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि खादी बोर्डका अेक प्रतिनिधि हाथ-करघा बोर्डमें और हाथ-करघा बोर्डका अेक प्रतिनिधि खादी बोर्डमें रहे।

खादी बोर्ड और कम्प्यूनिटी प्रोजेक्ट्स अेडमिनिस्ट्रेशनकी प्रवृत्तियोंमें सहकार साधनेके संबंधमें बोर्डके अध्यक्षने अून निर्णयोंकी चर्चा की, जो कि शिमलामें अभी कुछ ही दिन पहले हुआ प्रोजेक्ट डेव्लोपमेन्ट कमिशनरोंकी परिषद्में लिये गये हैं। अुन्होंने बतलाया कि बोर्ड खादी और ग्रामोद्योगोंके लिये 'ब्लॉक' के स्तर पर कार्यकर्ता तैयार कर सकता है। प्रोजेक्ट अेडमिनिस्ट्रेशनको हर वर्ष ५०० प्रशिक्षित व्यक्तियोंकी जरूरत होगी। अब यह बात बोर्डको सोचना चाहिये कि वह अिसमें क्या मदद कर सकता है।

अिस विषय पर बादमें बोर्डके सदस्योंने पूरी चर्चा की और सवालके सारे पहलुओं पर विचार किया। यह निर्णय हुआ कि अिस साल नासिकमें बोर्डके केन्द्रीय विद्यालयमें १०० प्रशिक्षार्थी लिये जायं और अिस तरहकी तालीमकी व्यवस्था दूसरे केन्द्रोंमें कर सकनेकी संभावनाओंकी जांच की जाय।

(अंग्रेजीसे)

सी० के० नारायणस्वामी

भूदान-यज्ञ

विनोबा भावे

कीमत १-४-०

डाकखर्च ०-५-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-१४

www.vinoba.in

गांवकी जमीन गांवकी हो

[ता० १-६-५५ को विक्रमपुर पड़ाव (अुत्कल) पर दिये गये प्रार्थना-प्रवचनसे]

मैंने सुना कि यहां पर कुछ तेलुगू भाषा बोलनेवाले लोग हैं, तो यह जानकर मुझे खुशी हुई। भूदान-यज्ञका आरम्भ ही तेलंगानामें हुआ था जहां सब लोग तेलुगू बोलते हैं। चार साल पहलेकी बात है। अप्रैलका महीना था। मैं नलगुंडा और वारंगलमें घूम रहा था। छोटे-छोटे गांवोंमें भी हमारा जाना हुआ था। वह गर्म गुल्क है। बाहरकी गर्मी वहां पर है ही, लेकिन अन्दरकी गर्मी भी बहुत ज्यादा है। वहां पर हजारों लोगोंकी कल हो चुकी थी, सारे भूमिवाले भयभीत थे; बहुतसे लोग जंगलमें छिपे हुए थे और बहुतसे जेलमें थे। सरकारकी सेना अिधर-अुधर घूम रही थी। कम्प्युनिस्ट भी जंगलमें पड़े रहते थे और रातमें आकर कुछ काम करते थे। तो लोगोंको रातमें अुनकी तकलीफ होती थी और दिनमें सरकारके सिपाहियोंकी तकलीफ होती थी। अिस तरह दोनोंके बीच लोग पीसे जा रहे थे। अैसे वातावरणमें चंद लोगोंके साथ हम वहां पर घूम रहे थे। बिल्कुल जंगलोंमें भी जो गांव थे वहां भी हम पहुंचे थे, क्योंकि हम चाहते थे कि सब लोगोंके साथ हमारी बातचीत हो।

वहांके कम्प्युनिस्टोंको हमने समझाया कि भाअियों, गरीबोंका काम तो हम भी करना चाहते हैं। परन्तु आप अपना तरीका बदलेंगे तो आप और हम अेकसाथ होकर हिन्दुस्तानमें काम करेंगे। सरकारके सिपाहियोंको हमने समझाया कि अगर शेरोंकी शिकार करनी होती तो शिकारसे काम बनता। परन्तु वीरोंकी शिकार नहीं होती है। अुनका विचार समझना होता है। अिस-लिये केवल हिंसासे कम्प्युनिस्टोंका मुकाबला नहीं हो सकता है। वहांके जमींदारोंको हमने समझाया कि भाअियों, यह सारा तुम्हारे हाथमें है। तुम्हें गरीबोंके साथ रहना है तो अुन्हें क्यों पीसते हो। अुनके साथ प्रेमसे रहो। जमीनवाले तो बेचारे डरे हुए थे अिसलिये गांव छोड़कर शहरमें भाग गये थे। हमने अुनको समझाया कि हमारे साथ गांवमें चलो, डरो मत। हम तुम्हारा और गांववालोंका प्रेम बना देंगे। हमने गांववालोंको समझाया कि आपकी अुनके खिलाफ कोअी शिकायत है तो अुनको डराना ठीक नहीं है। अपनी शिकायत पेश कीजिये। अिस तरह हमने किसान, जमींदार, सिपाही और कम्प्युनिस्टको समझाया। आखिर दो महीनेकी हमारी मुसाफिरीमें हमको वहां पर बारह हजार अेकड़ जमीन मिली। तब लोगोंको कुछ अितमीनान हो गया कि शान्ति और प्रेमसे कुछ काम हो सकता है। अिस तरहसे तेलुगू मुल्कमें अिस कामका आरम्भ हुआ। तो हम चाहते हैं कि यहां पर जो तेलुगू बोलनेवाले लोग बैठे हैं वे अिस आन्दोलनके मर्मको समझ लें और अिस कामको अुठा लें।

हमारी सभाओंमें हजारों भूमिहीन आते हैं और वे हमारा संदेश सुनते हैं कि भूमिका मालिक तो भगवान् ही हो सकता है, दूसरा कोअी नहीं हो सकता। जैसे हवा, पानी और सूरजकी रोशनी भगवान्की देन है, अुसी तरह जमीन भी भगवान्की देन है। अिसलिये अुस पर किसीका दावा नहीं हो सकता। अब भूमिहीन लोग भी जाग गये हैं। तो यह असम्भव है कि ये सारे लोग जाग जायं और फिर भी दबे रहें, जैसे कि आज तक थे। और हम चाहते भी नहीं कि वे दबे रहें। हम नहीं चाहते कि हिन्दुस्तानमें कोअी भी दवा रहे या कोअी भी दूसरोंको दबाये। आजादीका अर्थ हम यह करते हैं कि जिस देशमें न कोअी डरता है, न कोअी किसीको डराता है, न कोअी किसीसे दबता है न कोअी किसीको दबाता है, वह देश आजाद है।

स्वराज्यके माने हैं कि हम किसीसे दबें नहीं और किसीको दबायें नहीं। हम अंग्रेजोंसे दबते थे और हरिजनोंको दबाते थे। जिस तरह दोनों प्रकारकी गुलामी थी। बापूने हमें सिखाया कि हमें हरिजनोंको दबाना नहीं चाहिये और अंग्रेजोंसे दबना नहीं चाहिये। इसी तरह हम नहीं चाहते कि हिन्दुस्तानके आजाद होनेके बाद यहां कोई भी शरूस दबा रहे। आजादीके बाद हमारा यह धर्म हो जाता है कि हम जमीनका बटवारा करें और भूमिहीनोंको जमीन दें। गांवकी जमीन गांवकी बनायी जाय और भूमिकी मालकियत मिट जाय।

विनोबा

हरिजनसेवक

२३ जुलाई

१९५५

अगली शिक्षा-योजनाकी रूपरेखा

केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालयने दूसरी पंचवर्षीय योजनामें शामिल करनेके लिये अंक १०८० करोड़ रुपयेकी कामकी योजना पेश की है। दूसरी पंचवर्षीय योजनाकी रूपरेखाकी तरह इसे भी अतिशय महत्वाकांक्षी बताया जाता है। आश्चर्यकी बात है कि योजना-कमीशन, हालांकि वह दूसरी पंचवर्षीय योजनाकी अपनी प्रस्तावित रूपरेखामें वही दोष नहीं देखता, शिक्षाकी अपर्युक्त योजनामें यह दोष बताता है। वह शिक्षा-मंत्रालय द्वारा पेश की हुयी रूपरेखाको स्वीकार नहीं करता और कहता है कि दूसरी राष्ट्रीय योजनामें शिक्षाके लिये ५०० करोड़से अधिक रुपये नहीं निर्धारित किये जा सकते। योजना-कमीशन दूसरे विभागोंकी योजनाओंके लिये कूते गये खर्चमें काटछांट करनेमें तभी सफल हो सकता है, जब वह अपनी योजनाकी रूपरेखामें सुधार करे। बेशक, इस रूपरेखामें विदेशी मदद और मुश्किलसे प्राप्त होनेवाली आयके बारेमें बड़े बड़े हाथी किले बना लिये गये हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसमें घाटेके बजट पर आधार रखा गया है, जो वास्तवमें घाटा ही है, सच्चा बजट नहीं।

अपर जिसकी चर्चा की गयी है वह शिक्षा-योजनाकी रूपरेखाका केवल अंक पहलू है। उसके बारेमें ज्यादा मौजू सवाल तो यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजनाके दौरानमें दरअसल क्या क्या जायेगा। मेरे पास इस समय उसका तफसीलवार कार्यक्रम बतानेवाली मूल योजना तो नहीं है। दैनिक अखबारों परसे मैंने जो कुछ समझा है, उसीके आधार पर मैं यह लिख रहा हूँ।

प्राथमिक शिक्षाके क्षेत्रमें बुनियादी शिक्षा दाखिल करनेकी राष्ट्रीय नीति पर अमल करनेका अधिक प्रयत्न किया जायगा। उसके साथ और मुख्यतः ज्यादा स्कूल खोलनेका प्रयत्न किया जायगा, ताकि १९६१ तक ६ से ११ वर्षकी बुझके लगभग ७५ प्रतिशत बालकोंको और ११ से १४ की बुझवाले लगभग ३० प्रतिशत बालकोंको स्कूलोंमें शिक्षा देनेकी व्यवस्था की जा सके।

माध्यमिक शिक्षाके क्षेत्रमें अमुक संख्यामें विविध हेतुओंवाले (मल्टी-परपज) हाथीस्कूल खोले जायंगे।

अच्छ शिक्षाके क्षेत्रमें सुझाया गया है कि युनिवर्सिटियां आजकी तरह चार वर्षके बदले ३ वर्षका प्रथम डिग्री कोर्स रखें।

और शिक्षाकी सारी अवस्थाओंमें शिक्षकों और अध्यापकोंका वेतन बढ़ानेके लिये अंकसा प्रयत्न किया जायगा। मेरे खयालसे यह अतिरिक्त खर्चकी अंक बड़ी मद होगी, जिसका स्वागत किया जायगा। लेकिन देशके शिक्षा-मंत्रालयोंको राष्ट्रको यह विश्वास दिलाता होगा कि शिक्षण-कार्य वास्तवमें प्रेम और प्रामा-

णिकतासे किया जायगा, आज जिस यांत्रिक ढंगसे शिक्षा-कार्यका संचालन किया जाता है उसमें जड़मूलसे परिवर्तन कर दिया जायगा और अंग्रेजी शिक्षाकी पुरानी पद्धतिके कारण, जो हमारी नापसन्दगी और उसे बदलनेकी अच्छाके बावजूद अभी तक जारी है, आज शिक्षाके क्षेत्रमें जो अनुशासनहीन व्यापारिक वृत्ति घुस गयी है उस पर नियंत्रण रखा जायगा। यह अंक अत्यन्त महत्त्वाका सुधार है, जो हमारी सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धतिमें किया जाना जरूरी है। शिक्षाकी किसी भी सच्ची योजनामें इस सुधारको प्रथम स्थान दिया जाना चाहिये। जब तक हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, शिक्षाके विस्तारको बढ़ानेवाली हमारी योजनायें केवल असफल ही रहेंगी; उनसे यह समस्या पेचीदा बनेगी और आजकी अन्धाधुन्धीकी हालतोंमें और ज्यादा अव्यवस्था और गड़बड़ी पैदा होगी। बेशक, मेरा मतलब शिक्षाके विस्तारकी निन्दा करना या उसकी आवश्यकतासे अन्कार करना नहीं है। मेरा कहना अितना ही है कि हमारी शिक्षाके बुनियादी सुधार या उसके गुणमें परिवर्तन करनेकी महत्त्वपूर्ण आवश्यकताके प्रश्नको उसे अलझाना नहीं चाहिये।

शिक्षाके विस्तार और सुधारके प्रश्न पर आते हुये यह कहना जरूरी हो जाता है कि रूपरेखामें बहुतसी बातोंको अंकसाथ हाथमें लेनेका कार्यक्रम पेश किया गया है। शिक्षा-मंत्रालयने जो कार्यक्रम पेश किया है, उसमें योजना-शक्ति और शैक्षणिक दीर्घदृष्टिका अभाव दिखायी देता है।

बुदाहरणके लिये, तीन सालके डिग्री कोर्सका सुधार उसके पहले स्कूलोंमें चलनेवाले १० या ११ सालके संशोधित शिक्षणकी आखिरी मंजिल माना जा सकता है। स्कूलोंके शिक्षणमें भी अम्यास-क्रम और संगठनकी दृष्टिसे सुधार होना चाहिये। कमसे कम कहा जाय तो ग्रान्टका प्रलोभन देकर युनिवर्सिटियोंको असा सुधार करनेके लिये तैयार करना व्यर्थ होगा, जिसे करनेकी उनकी अच्छा नहीं दिखायी देती। इससे बिना कारण उनकी व्यवस्थामें गड़बड़ी पैदा होगी और बदलेमें तुरन्त कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि केवल ४ सालके बदले ३ साल कर देनेसे पढ़ाईके समयमें ही परिवर्तन होगा; वस्तुतः गुणकी दृष्टिसे कोई ठोस लाभ नहीं होगा। स्कूलकी ११ सालकी शिक्षामें ठोस सुधार करनेके बाद अंक वर्षकी बचतवाला यह सुधार किया जा सकता है। स्कूलकी शिक्षामें सुधार हो जाने पर युनिवर्सिटीकी शिक्षामें स्वभावतः यह सुधार हो जायगा और वह अचित भी माना जायगा। आज यह सुधार करनेका मतलब होगा पुराने कमीशनोंकी सिफारिश पर बिना सोचे-समझे अमल करना, जिन्होंने अपने मुख्य विचार ब्रिटिश नमूनोंसे लिये थे। आज उनके अिन विचारोंकी कोजी अपयोगिता नहीं है। हमें अपने अनुकूल शिक्षा-पद्धतिका निर्माण करना होगा, जो देशके सारे लोगोंके — जिन्हें हम स्कूलों और युनिवर्सिटियोंमें शिक्षा देना चाहते हैं — हितों और जरूरतोंको पूरा कर सके। ब्रिटिश शासनकालमें केवल देशके कुछ वर्गोंकी सीमित जरूरतोंका ही खयाल रखा गया, जिनकी संख्या देशकी समस्त प्रजाके १० प्रतिशतसे भी कम थी। इसलिये यदि शिक्षा-योजनाकी रूपरेखा पहले किये जाने लायक कामों पर पहले ध्यान दे और तीन सालके डिग्री कोर्स जैसे सुधारोंको आगेके लिये मुलतवी कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा।

बेशक, सबसे पहला करने जैसा काम संविधानके उस आदेशमें बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि १९६० तक सब बच्चोंके लिये १४ सालकी बुझ पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षाकी व्यवस्था की जाय। शिक्षा-योजनाकी रूपरेखा कबूल करती है कि १९६० तक असा करना असंभव है। और अगर योजना-कमीशन १०८० करोड़के उसके कार्यक्रममें काटछांट कर देता है तब

तो वह काम और भी असंभव हो जायगा। तब क्या किया जाय? यह समस्या अतनी ही भारी और विकट है, जितनी कि आर्थिक क्षेत्रमें हमारी बेकारी और अर्ध-बेकारीकी भयंकर समस्या है। संघ-सरकारकी दूसरी पंचवर्षीय योजनाकी रूपरेखा बेकारीके विषयमें अुसी तरह अपनी हार कबूल करती है, जिस तरह शिक्षा-मंत्रालय सार्वत्रिक राष्ट्रीय शिक्षाके बारेमें अपनी हार कबूल करता है।

यहीं हमारे राष्ट्रपिता बुद्धिमानी और दूरदर्शितामें केवल शैक्षणिक या आर्थिक क्षेत्रके सरकारी अथवा गैर-सरकारी निष्णातोसे बहुत आगे बढ़ गये थे। अुन्होंने बताया कि बुनियादी शिक्षा अर्थात् हाथ-अुद्योगों द्वारा दी जानेवाली शिक्षा ही अन्तमें आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि वह लोगोंकी जरूरतकी चीजें भी तैयार करेगी। इसी विचारके दूसरे अंगके रूपमें अुन्होंने कहा कि अिन अुद्योगोंको हमारे बेकार लोगोंको पूरा कामधंदा देना चाहिये और अिस तरह बुनियादी शिक्षाके नये विचारके बढ़ने और पनपनेके लिये आवश्यक सामाजिक भूमिका और वातावरणको निश्चित बनाना चाहिये।

यह खुशीकी बात है कि हम गांधीजीके अिस संपूर्ण प्रस्तावके आर्थिक या औद्योगिक भागको मानने लगे हैं, लेकिन शिक्षा-संबंधी अुनके सुधारको अभी हमने अुतना स्वीकार नहीं किया है। कहनेका मतलब यह है कि संघ-सरकारकी दूसरी पंचवर्षीय योजनाकी रूपरेखाने, कितनी भी अनिच्छासे क्यों न हो, छोटे पैमानेके अुद्योगोंको योजनाका अभिन्न अंग मान लिया है, जब कि शिक्षा-योजनाकी रूपरेखा कितना ही चाहने पर भी अुस हद तक असा नहीं कर सकती। क्योंकि हमारी शिक्षित दुनियाके अूपरी स्तरके लोग अिस सुधारको आज भी सन्देहकी दृष्टिसे देखते हैं और हमारी संपूर्ण शिक्षाके नवनिर्माण और पुनर्गठनके प्रश्न पर गहराबीसे विचार नहीं करते।

हमें अिस बातका ध्यान रखना चाहिये कि शिक्षा अब अेक छोटेसे वर्गकी प्रवृत्ति नहीं रह सकती। संविधानमें देशके प्रत्येक नागरिकका काम, शिक्षा और बेकारीमें सरकारी सहायता वगैरा पानेका अधिकार स्वीकार किया गया है। शिक्षा-संबंधी अधिकार अुंचेसे अुंचे दर्जेकी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करनेका अधिकार है, अिसलिये जो भी योग्य हो अुसे आर्थिक स्थिति, लिंग, वर्ग या धर्मके किसी भेदभावके बिना पूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिये। यह अधिकार 'डोल' और आर्थिक सहायता द्वारा नहीं दिया जा सकता। वह अुस सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्थाका स्वाभाविक परिणाम होना चाहिये, जो अब हम कायम करेंगे। इसी सन्दर्भमें बुनियादी शिक्षा तथा ग्रामोद्योग और गृह-अुद्योग अेक अखण्ड कार्यक्रम बनाते हैं और हमारे लिये अनिवार्य बन जाते हैं, अगर हम सचमुच देशमें अेक स्वस्थ, स्वावलंबी और समृद्ध नयी व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं। शिक्षा-मंत्रालयको अिस सिद्धान्त पर और अिस विशाल दृष्टिसे अपने कामकी योजना बनानी चाहिये। यह आवश्यक पैसेकी अुसकी मांगको निर्विवाद और अनिवार्य बना देगा। जो लोग काम और शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अुन्हें स्वस्थ और सुव्यवस्थित राज्यमें अिनसे अिन्कार नहीं किया जा सकता। अैसे लोगोंको दोनों चीजोंका विश्वास दिलानेके लिये भारत-सरकारको दूसरी पंचवर्षीय योजनाके साथ राष्ट्रीय पुन-निर्माणके लिये बताये अुअे गांधीजीके अुस कार्यक्रमका मूल्य भी समझना चाहिये, जो अुन्होंने शिक्षा और ग्रामोद्योगोंके संबंधमें बताया है।

१३-७-५५
(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

सेवा और भक्ति

[ता० १६-५-५५ को पुडामारी पड़ाव (अुत्कल) में दिये गये प्रार्थना-प्रवचनसे।]

बहुत दफा यह पाया जाता है कि हिन्दुस्तानका भक्तिमार्ग सेवापरायण नहीं है। आज तक वह मूर्ति, ध्यान-परायण रहा है। लेकिन अब जमाना आया है कि भक्तिमार्गको अपना मुख्य स्वरूप ही सेवापरायणताका बनाना चाहिये। अेक जमाना था जब अैसी योजना की गयी थी कि गांवमें कोअी मध्यवर्ती मंदिर हो और अुस मंदिरकी सेवा अिस तरहसे चले कि गांवके सामने सेवाका आदर्श अुपस्थित हो। वह तो अेक किंडर गार्टनका स्कूल खोला गया था। जैसे मंदिरमें सुबह भगवान्के जागनेका समय हुआ तो चौघड़ा बजता था और गांववालोंसे कहा जाता था कि हे भगवानो जागो। तो क्या पत्थरका भगवान् सोता है या जागता है? लेकिन सुबह सब लोगोंको जागनेके वास्ते यह अेक नाटक किया जाता था। फिर दौपहरको भगवानको प्रसाद चढ़ानेका समय आता था, तब आरती होती थी तो सारे गांववाले वहां पर आकर दर्शन करते थे और फिर घर जाकर भोजन करते थे। तो गांवके लोगोंके भोजनका अेक निश्चित समय होता था। फिर शामको भगवानकी आरतीका समय होता था, तो गांववाले अपना सारा काम बन्द करके मंदिरमें जाते थे और आरतीके समय सारे भाअी अिकट्टा होते थे। फिर शामको भगवान्के सोनेका समय होता था तो अुनको सुलानेके लिये गीत गाय जाते थे। सारे लोग अुसमें सम्मिलित होते थे और भगवान्का नाम लेकर घर जाकर सोते थे। तो सोनेका भी अेक निश्चित समय होता था। अिस तरह सारे गांवकी जो दिनचर्या होनी चाहिये अुसका नियमन मंदिरकी दिनचर्यासे होता था। अिस तरह मंदिरके जरिये लोगोंको शिक्षा मिलती थी।

लेकिन आज तो यह होता है कि मंदिरमें भगवान्के नैवेद्यका समय हुआ तो भी जिस मनुष्यके घरमें खानेकी चीज ही नहीं है, वह भगवान्को क्या खिलायेगा? जब देशकी यह हालत हो कि देशके लोग भूखे, नंगे और रोगसे पीड़ित हों तब अुनकी सेवामें लग जाना ही भक्तिमार्गका सर्वोत्तम कार्यक्रम है। मुझे खुशी हो रही है कि वैष्णव संप्रदायके अेक सेवकने यह महसूस किया कि भूदान-यज्ञके कामके जरिये भक्तिमार्गका प्रसार ठीक तरहसे हो रहा है। हम लोगोंको बार-बार यही समझाते हैं कि हमारे आसपास जितने प्राणी हैं, वे सब हमारे स्वामी हैं और हम अुनकी सेवाके लिये जन्मे हैं। यह स्वामी-सेवक भाव भक्तिमार्गकी आत्मा है। जहां हम भूतमात्रको हरिस्वरूप देखते हैं, अुनको स्वामी समझते हैं और अपनेको सेवक, वहां हमारी हरअेक कृति भक्तिमार्गकी बन जाती है। अिसलिये भक्तोंको बहुत नम्र होना चाहिये। अुनमें आपस-आपसमें अत्यन्त प्रेम होना चाहिये, और अुनको यह महसूस होना चाहिये कि हम भगवान्की सेवामें लगे हैं। अिसलिये किसी भी प्रकारके राग-द्वेषको मनमें स्थान नहीं देना चाहिये। लोग हमारे जीवनकी कसीटी भक्तोंके जीवनसे करेंगे और देखेंगे कि यह जो भूदानमें लगे अुअे कार्यकर्ता हैं, अुन्होंने अुसके अनुसार अपना जीवन और हृदय बनाया है या नहीं। अिसलिये हमें तनिक भी संदेह नहीं है कि अगर हम अपने जीवनमें जागृति रखेंगे तो भूदानका काम अिनके जसा फैलेगा।

चिनोबा

सर्वोदयका सिद्धान्त

कीमत ०-१०-०

डाकखर्च ०-४-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४

कागजी मुद्रा और बैंकोंकी माया

श्री शंकराचार्यने मायाकी व्याख्या करते हुअे असे तज्ज्ञकी अपुमा दी है जो वेमेल वस्तुओंको आपसमें मिला देता है। बैंकोंके सहयोगसे कागजी मुद्राने यही चमत्कार कर दिखाया है। जिस चीजकी अुम्र ज्यादासे ज्यादा दो सालकी या लगभग अितनी ही हुआ करती थी, अुसे अिन दोनोंने मिलकर अमर कर दिया है। अुन्होंने मनुष्यमें परिग्रहकी वृत्तिको तीव्र करके पूंजीवादके राक्षसको जन्म दिया है, जो विपुल मात्रामें अुत्पादन करनेकी क्षमता तो रखता है, पर संपत्तिका अत्यंत विषम वितरण करता है।

लगभग दो सौ साल पूर्व तक बड़े-बड़े भू-स्वामियोंकी संपत्ति अनाज, कपास या खेतीकी दूसरी वस्तुओं और पशुओंके रूपमें हुआ करती थी। अनाज बहुत हुआ तो दो साल तक टिकता था और पशु १० से १५ साल तक। और वे खतम हों अुसके पहले ही अुसे अुनका अुपभोग या अुपयोग कर लेना पड़ता था। मान लीजिये कि अुसकी वार्षिक आय १०० गाड़ी घान थी। अिसमें से अुसका परिवार अपने भोजनके रूपमें १० गाड़ी चावल खर्च करता और करीब १० गाड़ी सरकारी करके रूपमें चला जाता था। बाकीका वह क्या करता था? यह अधिक अनाज घरके नौकर, माली, खेतिहर मजदूर, बुनकर, घोषी, नाजी, कुम्हार, बढ़ाई आदिको अुनकी सेवाओंके बदलेमें दिया जाता था। और अेक अंश कलाकारोंको आश्रय देनेमें खर्च होता। बाकी जितना बचता वह स्थानीय सार्वजनिक कार्योंमें दानकी तरह दिया जाता; अुदाहरणके लिये मंदिर, तालाब आदि बनवाने और अिसी तरहके दूसरे कामोंमें खर्च होता जो सबके काममें आते थे। यदि वह असा नहीं करता तो सारा अनाज पड़ा-पड़ा बेकाम हो जाता था।

अिस तरह वस्तुतः वह अपनी संपत्तिका ट्रस्टी होता था, क्योंकि अुसकी आयका लगभग ८० प्रतिशत विविध प्रकारकी सेवाओंके लिये गांवमें ही बंट जाता था। संपत्तिका संग्रह करना अुसके लिये आसान नहीं था। अुस समय चांदी और सोनेके सिक्के ही मुद्रा थे और अुनकी संख्या और मात्रा अेक सीमाके बाहर नहीं जा सकती थी।

लेकिन कागजी मुद्रा और व्यापारियोंकी सहायताके लिये बैंकोंके आगमनके साथ ही आर्थिक जीवनमें अेक बड़ा परिवर्तन अुपस्थित हुआ। अब जमींदारके लिये अपना ८० गाड़ी अतिरिक्त अनाज बेचना और जितनी बन सके अुतनी रकम बैंकमें लगाना संभव हो गया। अभी तक अुसके पास सीमित जमीन थी जिससे सीमित वार्षिक आय हुआ करती थी। अब जमीनके साथ अुसके पास प्रतिवर्ष वह अपनी चतुराईके जरिये जितना पैसा बचा सके अुतना पैसा भी रहने लगा। अभी तक संपत्तिके नाम पर अुसके पास कुछ अतिरिक्त अनाज हुआ करता था, जिसे अुसे सालमें खर्च कर डालना पड़ता था। लेकिन अब वह अपनी अिस संपत्तिको बैंकमें जमा की गयी बढ़नेवाली पूंजीका रूप देनेमें समर्थ हो गया। पहले अुसके अुत्तराधिकारियोंकी अुसकी जमीन ही मिलती थी। अब यह बैंककी पूंजी भी मिलने लगी। बैंकके आगमनके पहले तक अिस बातकी कोअी कल्पना भी नहीं कर सकता था।

बैंककी पूंजीके रूपमें मनुष्यकी संग्रहवृत्ति या लोभको अेक अच्छा बलवान् साथी प्राप्त हो गया। अब चूँकि लोभके अिशाेरे पर काम करना संभव हो गया, अिसलिये जमींदार अपना भरसक अतिरिक्त अनाज व्यापारीको बेचने लगा जिसे बैंककी बड़ी पूंजीका बल था। अनाजका अेक बड़ा अंश गांवके बाहर भी जाने लगा और गरीब देहातियोंके लिये वह अप्राप्य हो गया। सार्वजनिक अुपयोगके कार्योंकी, जैसे तालाब, मन्दिर आदि बनवानेकी प्रेरणा पहलेसे बहुत

कम हो गयी। गांवोंमें आधुनिक समयमें बनाये गये सार्वजनिक कुअें, तालाब, मन्दिर आदि देखनेमें नहीं आते।

अपनी संपत्ति अिस तरहके कार्योंमें लगानेके बजाय अब अुन्होंने अुसे पश्चिमकी नयी आकर्षक वस्तुअें खरीदनेमें लगाना शुरू कर दिया। अब वे अमेरिकाकी मोटरें, स्विट्जरलैंडकी हाथ-घड़ियां, अिंगलैंडका फैशनेबल कपड़ा और फ्रांस तथा जापानकी शौककी चीजें खरीदनेमें पैसा लगाने लगे। गांवके कारीगरोंकी अुपेक्षा होने लगी और अुन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया। गरीब लोगोंकी गरीबी और संख्या भी बढ़ने लगी।

पूरा विश्लेषण करने पर मालूम होगा कि अगर पूंजीवादको कागजी मुद्रा और बैंकोंकी जोरदार मदद न मिली होती, तो वह न तो अुत्पन्न हो सकता था और न पनप सकता था। निष्कर्ष यह है कि समाजवाद तब तक नहीं स्थापित किया जा सकता, जब तक कि पूंजीवादकी अिस जड़ पर कुठाराघात नहीं किया जाता। कागजी मुद्रा और बैंककी पूंजी दोनोंके जीवनकी मियाद अभी अपरिमित है; असा नहीं होना चाहिये। जमींदारों या अुद्योग-पतियोंके पास जो कागजी मुद्रा है, वह असलमें अनाज या कपड़ा आदि वस्तुओंकी प्रतीक है और अिन वस्तुओंका जीवन बहुत छोटा होता है। अिसलिये यह बिलकुल अुचित होगा कि कागजी मुद्राका जीवन भी दो-तीन वर्षका ही हो। अेक साल तक तो अुसकी कीमत कायम रहे, पर बादमें अुसे घटते जाना चाहिये और अुक्त मुद्दतके बाद वह खतम हो जानी चाहिये। जमीन या खान आदि हर साल अुपज देती हैं; कुदरतन् अुनकी अुम्र बड़ी होती है। लेकिन, जसा कि सुविदित है, अिमारतों, फंक्टरियों, यंत्रों आदिकी आयु अपेक्षया छोटी होती है, क्योंकि अुनकी अुपयोगिता और अिसलिये मूल्य हर साल कम होता जाता है। अिस तथ्यको अुद्योगपति और पूंजी लगानेवाले व्यापारी मानते हैं। तो फिर क्या वात है कि केवल कागजी मुद्राको—जो कि अनाज, कपड़ा आदि अल्पजमीनी वस्तुओंका ही प्रतिनिधित्व करती है—यह नियम न लगाया जाय? अुसकी कीमत भी अेक निश्चित मुद्दतके बाद घटने लगना चाहिये।

मेरा प्रस्ताव है कि नोटोंकी कीमत अेक साल या डेढ़ साल तक तो पूरी कायम रहनी चाहिये, पर बादमें वह प्रति मास दसवां हिस्सा कम होती जानी चाहिये और अिस तरह क्रमशः शून्य हो जानी चाहिये। अनाजकी कीमतोंमें क्या असा ही नहीं होता? यही बात बैंकमें जमा पूंजीको भी लागू होनी चाहिये। अेक निश्चित मुद्दतके बाद अुसकी कीमत कम होती जानी चाहिये।

मुद्रा और बैंक अुपयोगी वस्तुअें हैं, किन्तु अुनकी बुराअियोंका संशोधन होना चाहिये। अगर मुद्राको भी अनाजकी तरह अल्पजीवी बना दिया जाय तो संग्रहकी बुखअी खतम हो जाय। और विषम बंटवारेके दोष भी अपने-आप बहुत कम हो जाय।

बुढ़ापेमें अपनी और मृत्युके बाद अपने बच्चोंकी अरक्षितताका विचार भी संग्रहकी वृत्तिका अेक बड़ा प्रेरक कारण है, किन्तु अुसका विचार अलग करना पड़ेगा।

स्वामी आत्मानन्द

[आधुनिक व्यापार और पूंजी-नियोजनमें पैसा केवल विनिमयका साधन नहीं है, वह पूंजी भी है। पूंजीके रूपमें अुसका व्यवहार समाजके लिये अलग प्रकारका है। अूपर लेखकने जो कुछ कहा है, वह पैसेके अिस दूसरे अुपयोगके बारेमें है। अगर हम भारतके देहातोंमें विकेन्द्रित अुद्योगोंका निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें अिस बात पर गंभीर विचार करना चाहिये।

१६-३-५५

(अंग्रेजीसे)

-- म० प्र०]

आणविक शस्त्रास्त्र और मानव-सुख

अगर भारत अमरीकी मदद स्वीकार करता है तो आणविक शस्त्रास्त्रोंके निर्माण और विस्फोटके उसके विरोधमें कोभी नैतिक बल नहीं रह जाता। अगर हमारे विरोधमें नैतिक बल है, तो उसका अर्थ यह होना चाहिये कि हमने अमेरिकाकी सहायता लेना छोड़ दिया है। जब तक अिन जघन्य विस्फोटों और अमरीकी आर्थिक मददको अक-दूसरेके समकक्ष माना जाता है, तब तक तो जिसके सिवा और कोभी रास्ता नहीं है।

गुनाहको रोकनेवाली चीज बलका वास्तविक प्रयोग नहीं, बल्कि बलके प्रयोगकी घमकी है। जिसलिअे दोनों विरोधी पार्टियोंके पास आणविक शस्त्रास्त्रोंका होना अिस बातकी गारंटी नहीं है कि बातचीत और युक्तियां असफल हो जायं तो भी शान्ति कायम रहेगी। जनतंत्र राष्ट्रको यह बात समझ लेनी चाहिये। अगर तर्क और युक्तियां और अक-दूसरेसे मेल साधनेका प्रयत्न जनतंत्रकी बुनियाद है तो शस्त्रास्त्र उसके दुश्मन हैं। आणविक शस्त्रास्त्रोंको तो उसके लिअे और भी ज्यादा विघातक मानना चाहिये। अिन शस्त्रास्त्रोंके दोनों पक्षोंके पास होनेके कारण अक बाहरी संदिग्ध शान्ति शायद रहे, लेकिन सच्ची शान्तिके निर्माणमें अुनसे कोभी सहायता नहीं मिल सकती। दूसरी ओर पंचशीलमें अ-हस्तक्षेप और सह-अस्तित्वके अिन सिद्धान्तोंका समावेश हुआ है, वे शांतिकी रचनामें महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं। अिससे स्पष्ट हो जाता है कि जरूरत हृदयोंके परिवर्तनकी है, युक्ति-प्रयुक्तियों या शस्त्रास्त्रोंके परिवर्तनकी नहीं।

जापानने सन् १९४५ में अणुबमोंके भयानक संहारका कष्ट भोगा और अब वह प्रायोगिक विस्फोटोंके दुष्परिणाम भुगत रहा है। तामिलमें अक कहावत है कि वर्षा तो बन्द हो गयी, लेकिन बूदा-बांदी जारी रही। दोनोंसे मौसम बेमजा होता है। जापानियोंने अिस बातका विरोध किया है, लेकिन अुसका परिणाम कुछ नहीं निकला, यद्यपि अमेरिका जापानकी समृद्धिमें दिलचस्पी रखता मालूम होता है। मतलब यह हुआ कि लोग मरें, अुनके हाथ-पांव टूटें और वे अपाहिज हो जायं, अिस बातकी तब तक कोभी चिन्ता नहीं, जब तक कि नये नये बांध, पुल और सड़कें बनायी जा रही हैं, नयी फैक्टरियां खड़ी की जा रही हैं और अुन्हें नया काम-धंधा तथा अन्न दिया जा रहा है। प्रश्न यह है कि अगर लोग अपाहिज हो जाते हैं, तो अिन सारी सुविधाओंको भोगेगा कौन? आणविक शस्त्रास्त्र और आर्थिक मदद दोनों अक-दूसरेके सर्वथा विरुद्ध मालूम होते हैं। अगर अिन शस्त्रास्त्रोंके कारण मानव-जातिके संपूर्ण विनाशका भविष्य नजर आ रहा है तो फिर अिस बातका क्या मतलब रह गया कि खेतमें अन्नके दो दाने कम हों या हजार ज्यादा हों। यह स्थिति हमें अुस मनुष्यकी याद दिलाती है जिसने अपने पड़ोसीके घरमें पहले तो आग लगा दी और फिर अुसे बुझानेके लिअे अुस पर पानी भी डाला। जो लोग अुस हाथसे विदेशी मदद लेनेकी हिमायत करते हैं, जो मौका आने पर संहारके लिअे अुद्यत रहता है, अुनकी तुलना हम शराब-बन्दीके विरोधियोंसे कर सकते हैं। शराबबन्दीके विरोधी कहते हैं कि सरकार शराबबन्दी करके अपनेको लाखों रुपयोंकी आयसे वंचित कर रही है, जब कि अुन रुपयोंका राष्ट्रके कल्याणकी योजनाओंमें सदुपयोग किया जा सकता है। वे यह भूल जाते हैं कि शराबबन्दी खुद अक कल्याणकारी योजना है। विदेशी मदद लेकर या अुसके बिना ही जितने वर्ष लग जायं अुतने वर्षोंमें विकास करना कम खर्चीला पड़ेगा, बजाय अिसके कि हमें आणविक शस्त्रास्त्रोंके घातक परिणाम भुगतने पड़ें।

(अंग्रेजीसे)

आर० संतानम्

अम्बर-योजना व कार्य

अप्रैल १९५४ में अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग मंडलकी तरफसे बड़े पैमाने पर अक प्रदर्शनका आयोजन किया गया था, जिसमें अम्बर चरखेका प्रात्यक्षिक प्रदर्शन रखा गया था। अुस समय सर्व-सेवा-संघकी तरफसे जो प्रयोग चल रहा था, अुस परसे असा दीखता था कि अम्बर चरखेके पूरे सेटके दाम रु० २००-२५० होंगे; शहरमें बड़े कारखानोंमें अुसके अुत्पादनका आयोजन करना होगा; और अुसका अुपयोग ग्राम-स्वावलम्बनकी दृष्टिसे किया जा सकेगा। किसी अक ग्राममें ५-१० अम्बर सेट परिश्रमालयके द्वारा चलाये जायेंगे और कपड़के लिअे आवश्यक सूत गांवमें तैयार होगा।

१९५४ के अप्रैलके बाद १९५५ जून तक अंबर चरखेमें काफी सुधार होते रहे, अुसके दाम घटानेकी दृष्टिसे कोशिश चलती रही और दूसरी तरफ किसी शहरके बड़े कारखानेमें अंबर सेट बननेके बदले अुसके अुत्पादनका बहुत सारा हिस्सा गांवके बढ़ियोंसे या लुहार आदि कारीगरोंसे गांवमें ही बने, अिस दिशामें कोशिश होती रही। नतीजा यह आया कि आज अंबर सेटके दाम रु० २५० से ७०-७५ रुपये तक आ गये हैं। कुछ विशेष पुर्जे छोड़कर अंबर सेट आज गांवका बढ़ी बना सकता है। अंबर सेट बनानेका ५०-६० प्रतिशत काम गांवके कारीगर ही कर सकते हैं।

अिस तरह दाम घट जाने तथा चरखा सादा बन जानेके कारण घरेलू अुद्योगकी दृष्टिसे अंबर सेटका आयोजन हर परिवारमें करना संभव दीख रहा है। सर्व-सेवा-संघ ग्राम-स्वावलम्बनके बदले घरेलू स्वावलंबनकी दृष्टिसे अिसके प्रयोग कर रहा है।

२८ नवम्बर १९५४ को सेवामाममें सर्व-सेवा-संघकी सभामें नीचे लिखे अनुसार प्रस्ताव पास किया गया और अम्बर चरखेका प्रयोग व्यापक क्षेत्रमें और बड़े पैमाने पर करनेका आयोजन सर्व-सेवा-संघकी तरफसे करनेका तय हुआ। अुसके अनुसार अक योजना बनायी गयी। योजनाको सर्व-सेवा-संघकी जगन्नाथपुरीकी मार्च ३०, १९५५ की सभामें स्वीकृति दी गयी। संक्षेपमें वह योजना नीचे लिखे अनुसार है:—

(१) योजना काल ता० १-५-५५ से ३०-४-५६ तकका रहे।

(२) ८,५०० अम्बर सेट सर्व-सेवा-संघकी तरफसे बनाये जायं और देश भरमें करीब अक सौ केंद्र वस्त्र-स्वावलंबनकी दृष्टिसे चलाकर अम्बर चरखेकी कार्यक्षमता जांची जाय; केंद्र अलग अलग प्रांतमें खोले जायं, अलग अलग किस्मका कपास अिस्तेमाल करनेकी दृष्टि भी रखी जाय और आदिवासियोंसे लेकर बड़े शहरों तक समाजके अलग अलग स्तरमें अुसे चलानेका आयोजन अुन केंद्रोंके द्वारा हो।

(३) अंबर सेट क्षेत्र-स्वावलंबनकी दृष्टिसे ही चलाये जायं। बाजारमें खादी बिक्रीके लिअे कपड़ा फिलहाल न बनाया जाय।

अिस योजनाको सफल बनानेकी दृष्टिसे गत ४-६ महीनेमें नीचे लिखे अनुसार काम हुआ है:

(१) अंबर चरखेके यदि १०० केंद्र देश भरमें चलाने हों तो २५० कार्यकर्ताओंकी आवश्यकता होगी। अुस दृष्टिसे ६० कार्यकर्ताओंका अक शिक्षण-वर्ग १६ फरवरी, १९५५ को मगनवाड़ीमें शुरू हुआ और अुनका अभ्यास वर्ग तीन महीनेमें पूरा हो गया। अब वे अलग-अलग क्षेत्रोंमें अंबर-केंद्र चलाने व अधिक अनुभव पानेके लिअे भेजे गये हैं।

(२) हम आशा रखते हैं कि दिसंबर-जनवरीके पहले २५० कार्यकर्ताओंकी शिक्षण-व्यवस्था इस तरह हो जायगी और अतः आवश्यक कार्यकर्ता इस कामके लिये मिल जायेंगे।

हर महीने १,००० सेट बनाये जा सकें, इसके लिये लोहेके पुर्जे अिकट्टा करनेका काम और सीज़न्ड लकड़ी जुटानेका काम भी धीरे-धीरे बड़े पैमाने पर करनेका सोचा जा रहा है।

फरवरी १९५५ में मगनवाड़ीके अभ्यास-वर्गमें जो ६० विद्यार्थी शिक्षा पाकर तैयार हुए और संघके कुछ कार्यकर्ता इस प्रयोगमें पहले ही लगे थे, अतः सबके द्वारा संघके पुराने प्रयोग-केंद्र व नये केंद्र मिलाकर नीचे लिखी जगहों पर अम्बर-केंद्र अब तक शुरू हो चुके हैं:

केंद्र स्थान	जिला	प्रांत	अंबर-सेट देनेकी तारीख	अंबर-सेटकी संख्या
१. मंगरीठ	बुधनौर	उत्तर-प्रदेश	२०-४-५५	२५ सेट
२. रामचंद्रपुर	कटक	बुड़ीसा	१-४-५५	११ "
३. कौआकोल	गया	बिहार	३-५-५५	५ "
४. काठमांडू	काठमांडू	नेपाल	७-५-५५	३ "
५. चक-अस्लामपुर	मुंशिदाबाद	बंगाल	२८-५-५५	४ "
६. बारडोली	सूरत	गुजरात	९-३-५५	१ "
७. खादीग्राम	मुंगेर	बिहार	२६-५-५५	५ "
८. कुष्ठधाम, दत्तपुर	वर्धा	मध्य-प्रदेश	१५-५-५५	१ "
९. अंबक-विद्यामंदिर	नासिक	बंबली	१०-५-५५	३१ "
१०. हुबली	धारवाड़	बंबली	८-५-५५	१ "
११. मूल	चांदा	मध्य-प्रदेश	२०-५-५५	३ "
१२. मगनवाड़ी	वर्धा	"	१५-२-५५	६५ "
१३. कमेरपुर	मुरादाबाद	उत्तर-प्रदेश	९-५-५५	५ "
१४. सेवाग्राम	वर्धा	मध्य-प्रदेश	२-६-५५	१ "
१५. बिलीमोरा	सूरत	गुजरात		१२ "
१६. पोचमपल्ली	नलगोंडा	हैदराबाद	२४-६-५५	५ "
१७. गोपुरी	कोल्हापुर	बंबली	१-७-५५	२ "

१८० सेट

कुल १८० चरखे अिन केंद्रोंमें चल रहे हैं।

यह काम अन्यान्य केंद्रोंमें चले, और अंबर-सेटका उत्पादन भी उसी क्षेत्रमें हो, इस दृष्टिसे देशके विभिन्न स्थानोंसे दौ-ढाजी सौ बड़की-मिस्त्री आदि बुलाकर अन्हें अंबर-सेट बनानेकी जानकारी करा देनेकी योजना बनायी गयी है।

दिसम्बरके अंत तक करीब ४०-५० केंद्र शुरू हो जायंगे और ३,००० से ४,००० अंबर-सेट अतः केंद्रोंके द्वारा चलाये जायंगे।

योजनाकी मर्यादायें

अंबर चरखेका पूरा मॉडल आज तक १५-१६ बार बदल चुका है। मौजूदा मॉडलमें बिलकुल पहले बने मॉडलकी पहचान तक भी नहीं है। और आजका मॉडल भी नजदीकके भविष्यमें बदलनेकी संभावना है। इस परिस्थितिमें सर्व-सेवा-संघने यह मर्यादा बांध ली कि मार्च १९५६ तक सर्व-सेवा-संघकी तरफसे वेचनेकी दृष्टिसे अंबर चरखे न बनाये जायें, तथा दूसरे सरंजाम कार्यालय भी बेचनेके खयालसे अंबर चरखा बनानेका काम फिलहाल हाथमें न लें।

देश भरमें आज अंबर चरखेकी कार्यक्षमता और अुपयोगिताके बारेमें आशावाक्य परिस्थिति खड़ी हो गयी है। संस्थाओं तथा

व्यक्तियोंकी तरफसे कीमत देकर अंबर सेट खरीदनेकी मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। अतः सबसे हमारा अनुरोध है कि इस प्रयोगको अेक व्यापक परिमाणमें आजमानेका काम आज सर्व-सेवा-संघकी तरफसे हो रहा है, अुसकी आजकी गतिसे ही होने दें। इस रिसर्चमें यदि कोअी मदद कर सकें तो अुसकी हमें आवश्यकता है। जो कर सकें वे इस काममें हमारी मदद करें, अंसी अुनसे हमारी प्रार्थना है। आम लोगोंसे हम कहेंगे कि ६-८ महीनेके लिये अंबर चरखे खरीदनेकी वे अपेक्षा न रखें। यदि वह अेक अुपयोगी चीज सिद्ध होगा तो दुनियाके आगे आ ही जायगा।

मगनवाड़ी, वर्धा
४-७-५५

अ० वा० सहस्रबुद्धे
मंत्री

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ

हमारे विदेशी ग्राहकोंसे

कभी कभी हमें अपने विदेशी मित्रोंकी ओरसे 'हरिजन' साप्ताहिकोंके चन्दके रूपमें डाक द्वारा विदेशी मुद्राके नोट मिलते हैं। अपने बैंकसके जरिये रिजर्व बैंकसे हमें जाननेको मिला है कि विदेशी ग्राहकोंकी अपना चन्दा बैंकों द्वारा ही भेजना चाहिये, क्योंकि डाक द्वारा नोट भेजनेमें विदेशी विनिमय नियंत्रण संबंधी नियमोंका भंग होता है।

अिसलिये विदेशी मित्रोंसे हमारी प्रार्थना है कि वे अपना चन्दा हमें डाकसे सीधा न भेजते हुअे बैंकों द्वारा ही भेजें।

१४-७-५५

जीवणजी डा० देसाजी
व्यवस्थापक-ट्रस्टी

बुनियादी शिक्षा

गांधीजी

कीमत १-८-०

डाकखर्च ०-६-०

सच्ची शिक्षा

गांधीजी

कीमत २-८-०

डाकखर्च १-०-०

शिक्षाकी समस्या

गांधीजी

कीमत ३-०-०

डाकखर्च १-२-०

विद्यार्थियोंसे

लेखक — गांधीजी; संपा० — भारतम् कुमारप्पा

कीमत २-०-०

डाकखर्च ०-१२-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४

विषय-सूची

विषय-सूची	पृष्ठ
दूसरी योजनाका छूटा हुआ पहलू	मगनभाई देसाई १६१
गांव अेक परिवार बने	विनोबा १६१
तीसरे सेक्टरके लिये योजना	सी० के० नारायणस्वामी १६२
गांवकी जमीन गांवकी हो	विनोबा १६३
अगली शिक्षा-योजनाकी रूपरेखा	मगनभाई देसाई १६४
सेवा और भक्ति	विनोबा १६५
कागजी मुद्रा और बैंकोंकी माया	स्वामी आत्मानंद १६६
आणविक शस्त्रास्त्र और मानव-सुख	आर० सन्तानम् १६७
अम्बर-योजना व कार्य	अ० वा० सहस्रबुद्धे १६७
टिप्पणी :	

हमारे विदेशी ग्राहकोंसे

जीवणजी डा० देसाजी १६८